व्यक्तियों के पुनर्वास कार्य में विलंब, उपकरणों की आपूर्ति में विलंब, भू-खनन परिस्थितियों, आदि कठिनाई ।

विदेशी फर्मों को दिए गए ठेके

1651. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में कोयला क्षेत्र में विदेशी फर्मों को कितने ठेके दिए गए ;

(ख) कितने ठेके पूरे किए जा चुके हैं और कितने चालू हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इनके कार्यों की समीक्षा की है और उन्हें संतोषजनक पाया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार विदेशी फर्मों के बजाए भारतीय फर्मों को ये ठेके दिए जाने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० नयमेगौड़ा) : (क) गत दो वर्षों के दौरान कोयला क्षेत्र में विदेशी फर्मों को 23 ठेके दिए गए ।

(ख) उपर्युक्त 23 ठेकों में से 8 ठेके निष्पादित कर दिए गए हैं तथा शेष 15 के ठेके चल रहे हैं ।

(ग) और (घ) इन ठेकों के कार्य की प्रगति की गहन समीक्षा समय-समय पर कोयला कंपनी और सरकार के स्तर पर की जाती है । इन ठेकों की कार्य की प्रगति सामान्यतः संतोषजनक पाई गई है ।

(ङ) नई प्रौद्योगिकी को शुरू किए जाने तथा उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा में सुधार करने तथा कोयला को उच्चतर दर पर अधिप्राप्ति करने के लिए ऐसी विशेषज्ञता वाले अन्य देशों से चुनिंदा द्विपक्षीय सहयोग प्राप्त किया जाता है जब सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि आयात के लिए प्रस्तावित प्रौद्योगिकी और उपकरण देश में उपलब्ध नहीं हैं तथा यह कि सहयोगी देश द्वारा वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही हो ।

कोयला "वाशरियों" में सुधार

1652. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अच्छी किस्म का कोयला उपलब्ध न होने के कारण कई संस्थानों से कोयले का आयात करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अच्छी किस्म का कोयला देश में उत्पादित नहीं किया जा सकता है ;

(ग) यदि नहीं, तो विगत वर्षों से कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोयला वाशरियों में क्या-क्या सुधार किए गए हैं ;

(घ) इन कोयला "वाशरियों" में सुधार और विकास के लिए चालू वर्ष के दौरान क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ङ) मार्च, 1991 के दौरान देश में कोयला "वाशरियों" में अधिकतम और न्यूनतम कितने प्रतिशत राख सहित कोयला उत्पादन करने की क्षमता थी ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० नयमेगौड़ा) : (क) जी, हां । इस्पात मंत्रालय के अनुसार इस्पात संयंत्रों द्वारा कोयले का आयात केवल गुणवत्ता के आधार पर ही किया जाता है ।

(ख) अच्छे गुणवत्ता वाले उच्च ग्रेड के कोयले के भंडार देश में कोयले के कुल भंडार देश में कोयला के कुल भंडारों के के लगभग 12.5 प्रतिशत होने का अनुमान है । अधिकांशः अच्छे गुणवत्ता

वाले कोयले को पहले ही ऊपरी सीमों (हॉरीजन) से पहले ही उत्खनित कर लिया गया है और इसके परिणामस्वरूप देश में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले का उत्पादन सीमित मात्रा में रह गया है। कोककर कोयले के भंडार भी बहुत सीमित मात्रा में विद्यमान हैं और वाशरियों को दिए जाने वाले कच्चे कोयले में वर्तमान में राख की मात्रा 30 से 31 प्रतिशत के बीच में हैं।

(ग) से (ङ) कोल इंडिया लि० की विभिन्न कोयला कंपनियों के अंतगत 15 वाशरियां कार्यरत हैं। इन वाशरियों की कार्यचालन क्षमता प्रतिवर्ष 25.22 मि० टन की है। सरकार द्वारा 1985 में नियुक्त की गई एल्तेकर समिति ने विद्यमान कोयला वाशरियों में सुधार किए जाने के संबंध में कई उपायों की सिफारिश की थी ताकि 17% +0.5 प्रतिशत राख वाले राख के धुले हुए कोयले की इस्पात संयंत्रों को आपूर्ति का सुनिश्चय किया जा सके। वाशरियों के कार्य निष्पादन में सुधार किए जाने के लिए कोयला, कंपनियों ने तैयार किए गए अल्पावधि/दीर्घावधि उपायों के क्रियान्वयन के जरिए वाशरियों के आधुनिकीकरण का कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में किए गए कुछ उपाय नीचे दिए हैं :—(i) डि-शैलिंग संयंत्रों की स्थापना, (ii) फ्लोटेशन संयंत्रों की स्थापना; और (iii) वाशरियों का आधुनिकीकरण और उनमें सुधार। वाशरियों के आधुनिकीकरण किए जाने से संबंधित कार्यक्रम को मार्च, 1993 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

Marketing policy of coal

1653. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government propose to make major changes in the marketing policy of the Coal India Limited;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the present marketing policy of the Coal India Limited is having deficiencies due to which consumers are not getting coal supplies; and

(d) if so, by when the new changes in the marketing policy of the CIL will be introduced and consumers will get coal supplies adequately?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) to (d) Distribution policy for coal requires periodical reviews to adjust to the changing patterns of demand and supply in order to maximise consumer satisfaction. Under the existing distribution policy, deficiencies in supplies to consumers have occurred from time to time due to various factors. However, recently a paper on the subject has been prepared and the views of the State Governments on the paper have been invited. Changes would be made, as and when considered necessary, after examining the suggestions received in this regard.

Delay in execution of coal projects

1654. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of COAL be pleased to refer to the answer to Starred Question 148 given in the Rajya Sabha on the 2nd December, 1991 and state:

(a) what is the number of coal projects that were sanctioned after nationalisation with target date of completion;

(b) what is the number of out of these that have been completed;

(c) what is the number of project are still in various stages of implementation; and

(d) what are the reasons for delay in their completion?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) 82 coal mining projects, each costing Rs 20.0 crores and above, were sanctioned after nationalisation.

(b) Out of 39 projects due for completion by 1990-91, 25 projects have been completed. 2 projects have been withdrawn/suspended. One project, namely Gevre-OC due for com-